सूचना का अधिकार

343/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/1747-1786/2015-पीएमआर

दिनांक: 09/02/ 2015

कार्यालय ज्ञापन

2829/FS/15

डायरी संख्या
Dy. No. 633 /RTI Sec./2015 2/02/15
दिनांक/Date 7/02/15

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रमेशचंद्र जोशी से प्राप्त दिनांक 29.1.2015 का आवेदन-पत्र(358/15 -393 और 396 - 399)(40 पत्र), जो इस कार्यालय में दिनांक 4.2.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी0के0 शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रमेशचंद्र जोशी
विष्णुधाम मंदिर
साईधाम मंदिर, ठाकुर कामप्लेक्स
वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, कांदिवली(पूर्व)
मुंबई - 400 101

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

~~DCP(C)~~
~~USC(RS)~~

DCP(C)
US(Japan)
US(China)

16/2

Shr

Shr 16/2

13/2

US(RTI)

1751 — 6/2/15

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत सूचना पाने के लिए

आवेदन पत्र क्रमांक 387 /२०१५ दिनांक 29.1.15

सेवा में,

मा. केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी,
मा.प्रधानमंत्री महोदय का कार्यालय,
१५२, साऊथ ब्लॉक, रायसिन्हा हिल्स,
नई दिल्ली - ११० ०११

१)	आवेदक का पूरा नाम	:	श्री रमेशचंद्र जोशी अध्यक्ष , धर्म रक्षक महामंच अध्यक्ष, राष्ट्र रक्षक जनमंच
२)	पत्ता	:	श्री विष्णुधाम मंदिर, ठाकूर कॉम्पलेक्स, साईधाम रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४०० १०१
३)	अपेक्षित सूचना का विवरण	:	मा. प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमें भेजा पत्र संख्या आरटीआई/ १०२८२/ २०१४/ पीएमआर दि.२३/१/२०१४ लेकिन हमें मुंबई में दिनांक ३०/०१/२०१५ को मिले पत्र के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने दिनांक २१/१०/२००८ से दिनांक २५/१०/२००८ तक Japan and China का दौरा क्यू किया था ? दौरे में उनके साथ और कौन-कौन शामील थे ? इस दौरे के कारण भारत को क्या फायदा हुआ था ? और इस दौरे के कारण भारत सरकार ने जो रुपए १३,९५,११,०००.०० चुकाए है, वह रुपए किस-किस को चुकाया है ? और कौनसे स्वरुप में चुकाए है ? इससे संबंधित सुचना यदि भारत सरकार के पास हो, तो कृपया यह सभी सुचना हमें हिंदी भाषा में भेजने की कृपा करें ।
क)	संबध विभाग	:	इस आवेदन पत्र के द्वारा हमने जो सूचना माँगी है वह सूचना जिस किसी भी विभाग में हो वह विभाग
(i)	अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण	:	उपरोक्त क्रमांक ३ के अनुसार
(ii)	अवधि जिसके लिये सुचना अपेक्षित है	:	उपलब्ध अभिलेख के अनुसार
(iii)	अन्य विवरण	:	हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण भारतीय संविधान के अनुसार कृपया हमसे केवल राष्ट्रीय हिंदी भाषा में पत्राचार करने की कृपा करें। एवम् पत्राचार में हमारे आवेदन का उपरोक्त क्रमांक एवम् दिनांक का उल्लेख जरुर करने की कृपा करें।
४	मै कथन करता हूँ कि अपेक्षित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ८ के आधीन प्रकटीत कीये जाने से प्रतिबन्धित नही है और मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। यह आवेदन पत्र के साथ नियमो के अनुसार भारतीय पोस्टल ऑडर भेजे है। यह आवेदन पत्र हमने आपको मुंबई से स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा है। हमारा मोबाईल नंबर - 09870019990, 09821424410, 09987523450		

4-13829?

Diary No. 28126 & Date 04/02/15
Last Date For Disposal 04/03/15

IPO No - 10F 845531-2 10/-

भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 51 A. (A To K) के अनुसार भारत का नागरिक के नाते हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कर्तव्य ही हमारा धर्म है

(रमेशचंद्र जोशी)
आवेदक

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सूचना का अधिकार मामला

समयबद्ध

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
(चीन प्रभाग)

सं. ई/551/08/2015-आरटीआई

16.03.2015

सेवा में

श्री रमेशचन्द्र जोशी
विष्णुधाम मंदिर
साईधाम मंदिर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पूर्व)
मुंबई - 400101

विषयः सूचना का अधिनियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित दिनांक 29.1.2015 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे 09.02.2015 को आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चीन के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार हैः-

वो जानकारी संकलित करके इस पत्र के साथ जोड़ दी गयी है

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली – 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

Aniket G. Mandavgane

(अनिकेत गोविंद मांडवगणे), आईएफएस
अवर-सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री की आगामी जापान और चीन यात्रा के संबंध में विदेश सचिव और सचिव (पूर्व) द्‌वारा वार्ता

अक्तूबर 20, 2008

सरकारी प्रवक्ता (श्री विष्णु प्रकाश) : आप सभी को नमस्कार । प्रधानमंत्री की आगामी जापान यात्रा के बारे में आपको जानकारी देने के लिए विदेश सचिव यहां हैं । वह विदेश मंत्री लवरोव की यात्रा के बारे में भी बात करेंगे जो आज ही समाप्त हुई है । विदेश सचिव के दायीं ओर सचिव (पूर्व) बैठे हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं । वह 7वीं एएसईएम शिखर बैठक के लिए प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा के बारे में आपको जानकारी देंगे । सचिव (पूर्व) के दायीं ओर हमारे संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री जे एस मुकुल बैठे हैं । मेरे बायीं ओर संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया) श्री विजय गोखले बैठे हैं । विदेश सचिव और सचिव (पूर्व) तत्पश्चात् आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे ।

विदेश सचिव (श्री शिवशंकर मेनन) : सभी को नमस्कार । जैसा कि आप जानते हैं, एएसईएम शिखर बैठक के लिए बीजिंग जाने से पहले प्रधानमंत्री 21 से 23 अक्तूबर तक जापान की सरकारी यात्रा पर जाएंगे ।

प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की यह दूसरी द्‌विपक्षीय जापान यात्रा होगी और हमारी नियमित वार्षिक बैठक का हिस्सा है जिस पर दोनों देशों के बीच सहमति हुई है । और वस्तुत: पिछले चार वर्षों से यह जारी है । आपको याद होगा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री अबे अगस्त, 2007 में भारत आए थे ।

हमारे लिए भारत – जापान संबंध बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं, ऐसे संबंध जिसे हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं और पिछले तीन वर्षों से हम इन संबंधों को सामरिक और वैश्विक भागीदारी के रूप में वर्णित करने पर सहमत हुए हैं । उदाहरण के लिए पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री अबे 22 अगस्त, 2007 को यहां आए थे, हमने सामरिक और वैश्विक भागीदारी की रूपरेखा तैयार की थी; और हम उस विचार – विमर्श को जारी रखना चाहते हैं ।

इस यात्रा के हमारे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तारो आसो के साथ विचार – विमर्श शामिल है । वह भारत के पुराने मित्र हैं । वह विदेश मंत्री के रूप में भारत आ चुके हैं । प्रधानमंत्री दिसंबर, 2006 में जब जापान यात्रा पर गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की थी । विदेश मंत्री के रूप में जनवरी, 2006 में और अप्रैल, 2007 में वह भारत यात्रा पर आ चुके हैं । प्रधानमंत्री जापान के महामहिम सम्राट और साम्राज्ञी से भी भेंट करेंगे । जापान के विदेश मंत्री और एमईटीआई मंत्री, जापान के प्रमुख विपक्षी दल, डेमोक्रेटिक पार्टी, नई कोमैटो पार्टी जो संसद में सरकार की प्रमुख सहयोगी है, के प्रमुखों और वरिष्ठ एलडीपी नेताओं,पूर्व प्रधानमंत्री मोरी जिनका हमारे संबंधों के विकास में बहुत योगदान रहा है, से भी प्रधानमंत्री भेंट करेंगे ।

प्रधानमंत्री, जापान के शीर्ष चेम्बर कीडनरैन द्‌वारा आयोजित व्यापारिक लंच को संबोधित करेंगे जिसमें जापान के प्रमुख निगमों के अग्रणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे । वस्तुत: यह पहला अवसर है जब कीडनरैन द्‌वारा भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । हम भारत – जापान व्यापारिक नेता मंच की दूसरी बैठक भी आयोजित करेंगे । भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री मुकेश अंबानी कर रहे हैं । यह ऐसी दूसरी बैठक है । आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब जापान के प्रधानमंत्री यहां आए थे, ऐसी पहली बैठक आयोजित की गई थी ।

व्यापारिक नेताओं द्‌वारा आर्थिक और वाणिज्यिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को ठोस सुझाव / प्रस्ताव दिए जाने की संभावना है और वे अपनी सिफारिशें इस बार टोकियो में प्रधानमंत्रियों को देंगे ।

प्रधानमंत्री, जापान – भारत एसोसिएशन और जापान – भारत संसदीय मैत्री लीग द्‌वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जा रहे स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे । इन दोनों संस्थाओं ने अनेक वर्षों से इस संबंध को मजबूत बनाने के लिए काम किया है । पिछले कुछ वर्षों में जापान के साथ हमारे संबंधों में काफी सुधार आया है । इस वर्ष भी अनेक उच्चस्तरीय यात्राएं हुई हैं । जापान के विदेश मंत्री अगस्त में सामरिक वार्ता के लिए यहां आए थे ।

हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने जापान के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में वार्ता की थी । इस वर्ष के प्रारंभ में जापान के वित्त मंत्री यहां आए थे । हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी वहां जा चुके हैं । वाणिज्य और उद्‌योग मंत्री भी जापान जा चुके हैं । इस तरह बातचीत का स्तर बहुत ऊँचा ही नहीं है अपितु प्रगाढ़ भी है ।

हमने इस वर्ष अगस्त में जापान के मेरीटाइम स्वत: सुरक्षा बल के जलयानों के साथ – साथ रक्षा के क्षेत्र में भी आदान – प्रदान किए हैं । हमारे नौसेना प्रमुख अगस्त में जापान यात्रा पर गए थे । हम इन यात्राओं को जारी रखना चाहते हैं ।

व्यापार और निवेश में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इस वर्ष इसके 15 अरब डालर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। सन् 2010 तक हमारा 20 अरब डालर का लक्ष्य है और हम समझते हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी विचार – विमर्श और वार्ता कर रहे हैं।

हम उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार, ऊर्जा, नागरिक विमान सेवाओं जैसे कार्यात्मक मामलों आदि पर अलग से विचार – विमर्श करते हैं और इसमें काफी वृद्धि भी हुई है। हम संबंधों के चौतरफा विकास से बहुत संतुष्ट हैं। सन् 2004 के बाद सर्वाधिक जापानी ओडीए प्राप्त करने वाला भारत एक मात्र देश हैं। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष हमने कुल जापानी ओडीए का लगभग 30 % प्राप्त किया।

हमारी अनेक पहलें हैं जो चल रही हैं। इनमें से एक का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। यदि आपको याद हो, पश्चिमी और पूर्वी दोनों समर्पित फ्रेट कॉरीडोरों पर भी और दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर जो फ्रेट कॉरीडोर से जुड़ा है, पर भी बातचीत कर रहे हैं। हम जापान से अन्य संभावित भागीदारी अर्थात् ग्रीनफील्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉनॉजी, एनआईआईटी पर भी विचार – विमर्श करते रहे हैं।

हमारी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इन सभी मसलों पर प्रगति की समीक्षा करेंगे, इसमें और क्या किया जा सकता है, यह देखेंगे और मंत्रियों को, अधिकारियों को इसे आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक निर्देश देंगे।

यह दोनों प्रधानमंत्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर विचार – विमर्श करने का भी अवसर होगा। मैं समझता हूं यह एक ऐसा क्षेत्र है जिनमें हम दोनों की काफी रुचि है। हम दोनों ने सफलतापूर्वक मिलकर काम किया है और एशियाई क्षेत्रीय एकीकरण चाहे यह ईएएस हो अथवा कोई अन्य मंच, कार्य जारी रखना चाहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर भी हमारी समान राय है। जैसा कि आप जानते हैं हम संयुक्त रूप से सह - प्रायोजक हैं। हम जी-4 के सदस्य हैं; हम मिलकर काम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा हमारे संबंधों को और प्रोत्साहन देगी।

मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी होगी किंतु मैं समझता हूं कि पहले रवि आपको बीजिंग यात्रा के बारे में बताएं और तत्पश्चात् हम दोनों आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।

सचिव (पूर्व) श्री एन रवि : धन्यवाद।

अपनी जापान यात्रा पूरी करने के पश्चात् प्रधानमंत्री 7वीं एशिया – यूरोप बैठक जिसे एएसईएम शिखर बैठक भी कहा जाता है, में भाग लेने के लिए बीजिंग जाएंगे। वह 23 की शाम को बीजिंग पहुंचेगे। वस्तुत: 24 और 25 अक्तूबर, दो दिन के लिए शिखर बैठक आयोजित की जा रही है। दोपहर में स्वागत समारोह से इसकी शुरूआत होगी। सामान्य स्वागत समारोह और उद्घाटन समारोह के पश्चात् पहले दिन नेताओं के बीच अकेले में विचार – विमर्श होगा और तत्पश्चात् स्वागत रात्रिभोज होगा।

तत्पश्चात् अगले दिन अर्थात् शनिवार 25 अक्तूबर को तीन बंद बैठकें होंगी और दो बैठकों के पश्चात् वर्किंग लंच होगा जहां सभी नेता

तत्पश्चात् अगले दिन अर्थात् शनिवार 25 अक्तूबर को तीन बंद बैठकें होंगी और दो बैठकों के पश्चात् वर्किंग लंच होगा जहां सभी नेता
अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय [illegible] विचार – विमर्श के लिए एकत्र होंगे। शनिवार शाम को लगभग 3.30 बजे समापन समारोह होगा और तत्पश्चात् लगभग 5 बजे के आसपास शिखर बैठक संपन्न हो जाएगी।

जैसा कि आपमें से अधिकांश लोग जानते हैं, एएसईएम में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य हैं – यूरोपीय आयोग भी एएसईएम प्रक्रिया का सदस्य – और एशिया की ओर से हमारे 10 आसियान सदस्य हैं, तीन उत्तर-पूर्व एशियाई सदस्य, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। [illegible] भारत [illegible] के स्तर पर इस शिखर बैठक में भाग ले रहा है।

[illegible]

करेगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह बैठक विशेष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर होगी जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है । नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति पर विचार – विमर्श किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा ये सभी मसले एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए हैं और काफी हद तक वे एक दूसरे में सन्निहित हैं और भविष्य के लिए नेताओं द्वारा विचार किए जाने के लिए ये गंभीर चुनौती पेश करते हैं ।

इस बैठक का एक उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच और अधिक सहमति तैयार करना, आदान – प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करना है । अगर चीजों को सही परिदृश्य में देखा जाए, यदि आप एशिया और यूरोप की जनसंख्या को जोड़ दें, इसका मतलब है कि एएसईएम प्रक्रिया के सदस्य राष्ट्र जो पृथ्वी की 50 % से अधिक जनसंख्या होगी ।

मैं सांख्यिकी का एक और उदाहरण देता हूं । भारत और एएसईएम के बीच व्यापार विशेष रूप से आगे बढ़ा है और आज भारत का लगभग 50 % व्यापार एएसईएम देशों के साथ है । इसलिए वर्तमान माहौल में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ।

धन्यवाद ।

प्रश्न : मेरे दो असंबद्ध प्रश्न हैं । पहला प्रश्न है कि क्या विदेश मंत्री श्रीलंका जा रहे हैं और यदि जा रहे हैं तो क्या इसके लिए तारीखों को अंतिम रूप दे दिया गया है ? और महोदय, कल नियंत्रण रेखा पर शुरू हो रहे व्यापार के बारे में पुंछ में कुछ भ्रम है । स्पष्टत: दूसरे पक्ष के व्यापारियों ने कहा है कि वे तैयार नहीं हैं और अधिकारियों में कुछ भ्रम है कि क्या कल पुंछ – रावलकोट मार्ग पर व्यापार आगे बढ़ेगा ? क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे

विदेश सचिव : विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा के बारे में, मैं समझता हूं कि रिपोर्टें वास्तविकता से आगे निकल गई हैं । कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है; अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं किया गया है । केवल संभावना का उल्लेख किया गया है लेकिन इस समय कुछ भी निश्चित नहीं है । मैं उम्मीद करता हूं कि संभवत: कुछ उच्चस्तरीय आधिकारिक विचार – विमर्श होगा, हो सकता है श्रीलंका के गणमान्य व्यक्ति स्थिति पर विचार करने के लिए यहां आएं और तब हम उस पर ध्यान देंगे । किंतु अभी कुछ निश्चित नहीं है ।

पुंछ – रावलकोट से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न, हमने पूरी व्यवस्था कर ली है । हमारी ओर से पूरी तैयारी है । पाकिस्तान की ओर से मेरा विश्वास है यह कहा जा रहा है कि क्या इसमें कुछ विलंब किया जा सकता है । वे बात कर रहे हैं और विचार – विमर्श कर रहे हैं और वह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस रूट को खोलने को स्थगित करने की आवश्यकता है अथवा नहीं अथवा क्या वे कल ही इसे खोल सकते हैं । अपनी ओर से हम तैयार हैं और हम इसे खोलने की उम्मीद करते हैं ।

प्रश्न : मेनन साहब, कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और आस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए लोकतंत्र का एक समूह बनाने का विचार रखा गया था और कुछ समय तक यह शांत रहा और किसी ने भी इसे स्पष्ट करने में रुचि नहीं ली । क्या इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के कोई अवसर हैं ? अथवा इसे हमेशा के लिए शांत कर दिया गया है ? धन्यवाद ।

विदेश सचिव : क्या मुझे अब स्पष्ट करना चाहिए ? मैं नहीं जानता । स्पष्ट रूप से मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है । मैं निश्चित नहीं हूं । मैं पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता कि क्या विचार किया जाता है अथवा विचार – विमर्श का परिणाम क्या होगा । किंतु जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसे किसी समूह अथवा ऐसी किसी व्यवस्था के बारे में बात करने के प्रति काफी सजग रहे हैं । स्पष्टत: हमारे लिए आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अधिक प्राथमिक संरचना एक खुली संरचना है जो लोकतांत्रिक हो जहां हम सभी की सुनी जाए और जहां हम मिलकर काम करें । और यही हमारी प्राथमिकता होगी ।

प्रश्न : जैसा कि आप बात कर रहे हैं 26 को जब श्रीलंका का प्रतिनिधिमंडल आएगा, भारत को इस प्रतिनिधिमंडल से क्या उम्मीदें हैं ? विदेश मंत्री जब भी श्रीलंका जाएं, क्या विदेश मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र का दौरा करने की भी अनुमति मांगी है ?

विदेश सचिव : मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने से आगे की बात पूछ रहे हैं । हमने विदेश मंत्री की यात्रा के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है । हमने आपको नहीं बताया कि कोई प्रतिनिधिमंडल आ रहा है और कब आ रहा है । मैंने आपको यही बताया था कि ऐसी संभावना है । इसलिए हमें समय से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि क्या हो सकता है और यह कहना शुरू नहीं करना चाहिए कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है अथवा कोई कब जा रहा है । अभी ऐसा कुछ निश्चित नहीं है ।

प्रश्न : उनके कब आने की उम्मीद है ?

विदेश सचिव : यह पूर्णत: काल्पनिक है । मैं आपको यह कैसे बता सकता हूं कि मैं किसी काल्पनिक घटना की क्या उम्मीद करता हूं ।

प्रश्न : एएसईएम से अलग क्या कोई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी ? क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री गिलानी से भी मिलेंगे ?

सचिव (पूर्व) : अभी तक द्विपक्षीय बैठकों के अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं । वस्तुत: मुख्य बैठक मेजबान के साथ होगी । अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं । वहां लगभग 40 नेता पहुंचेगे । हमें अनेक अनुरोध मिले हैं । इसलिए उन्हें क्रम से लगाने और यथास्थान रखने में समय लग रहा है । जैसे ही हम इसके बारे में निर्णय ले पाएंगे, हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे ।

प्रश्न : मेनन साहब, रूस, विश्व में वित्तीय स्थिति के संबंध में जी – 8 की वार्ता में भारत के शामिल होने का मजबूती से समर्थन करता रहा है। क्या श्री लवरोव के साथ भविष्य के बारे में इस पर विचार – विमर्श किया गया था जिसकी योजना बनाई गई है क्योंकि जी – 8 की बैठक में शीघ्र ही विचार – विमर्श हो सकता है ? क्या रूस और भारत ने संयुक्त रूप से कोई विचार व्यक्त किया है ? रूस, जी – 8 में भारत को शामिल किए जाने का समर्थन कैसे कर रहा है ?

विदेश सचिव : आपको बहुत बहुत धन्यवाद । जी हां । प्रधानमंत्री के साथ और विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के साथ विदेश मंत्री लवरोव की बैठक के दौरान यह मामला उठा था । दोनों ही बैठकों में उन्होंने विचार – विमर्श किया था कि दुनिया वित्तीय संकट और आर्थिक स्थिति जिसका हम सामना कर रहे हैं, के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है । हमारे प्रधानमंत्री ने मुख्यत: घरेलू प्रभावों पर संसद में 4 बजे वक्तव्य दिया था और भारत के रूप में हमें यह कैसे प्रभावित करेगी और आप इसे देख सकते हैं । किंतु विभिन्न प्रस्तावों पर कि दुनिया को इससे कैसे निपटना चाहिए – आप जानते हैं कि जी- 8 की विस्तृत बैठक में, जी-8 प्लस में अथवा शिखर बैठक में ऐसे अनेक विचार आए थे ।

हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत समाधान का हिस्सा होगा और इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने के लिए दूसरे देशों के साथ काम करने को तैयार है । किंतु जब संक्षिप्त तंत्र की बात आती है – इस तरह की शिखर बैठक, हम जो भी करते हैं – मैं समझता हूं कि हमारे दृष्टिकोण से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अच्छी तरह से तैयार हो । क्योंकि यदि यह अच्छी तरह से तैयार नहीं होता और यदि हम उम्मीदें बढ़ाते हैं और हम उन्हें पूरा नहीं करते तो यह संकट जो विश्वास के संकट के रूप में शुरू हुआ है और विकृत हो सकता है । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम विश्वास के इस संकट का समाधान करें हम जो भी करें, सावधानी से इसकी तैयारी करें ।

इसलिए हम अपने मित्रों, रूसी सरकार के और अन्य देशों के संपर्क में रहेंगे ताकि यह देख सकें कि यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है । किंतु इस स्तर पर यह कुछ जल्दबाजी होगी । अनेक प्रकार की बैठकों, अनेक तंत्रों के बारे में अनेक विचार हैं जिससे इस मसले का समाधान किया जाए ।

प्रश्न : मेनन साहब, चीन के साथ हमारी सीमा वार्ता की क्या स्थिति है ? क्या आप इस मसले पर कुछ आगे बढ़े हैं अथवा धीमी प्रक्रिया से आप निराश हैं ? आपने कई दौर की वार्ता की है । अंत में एक छोटा सा वक्तव्य होता है और कुछ नहीं ।

विदेश सचिव : मैं आपको एक दूसरा छोटा वक्तव्य देता हूं यदि आप चाहते हैं ।

प्रश्न : इससे कुछ और अधिक ?

विदेश सचिव : हम संतुष्ट हैं । हम समझते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं । विशेष प्रतिनिधियों की 12 बैठकों ने हमें काफी प्रगति करने में सहयोग दिया है । अभी हाल की बैठक इस महीने बीजिंग में हुई है । आपको याद होगा, जब हमने यह प्रक्रिया शुरू की थी, हमने कहा था कि हम प्रयास करेंगे और पहले मार्गदर्शी सिद्धांतों पर, सीमा समाधान के सामान्य सिद्धांतों पर सहमत होंगे । यह कार्य हो चुका है । हमने सीमा समाधान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों और राजनीतिक मापदंडों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं । अगला उपाय सीमा समाधान की रुपरेखा तैयार करना है और अभी हम यही कार्य कर रहे हैं । हम इस प्रक्रिया में लगे हैं और हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं । किंतु यह एक जटिल मसला है ।

यह ऐसा मसला नहीं है जिसका एक रात में समाधान कर लिया जाए । इस समस्या के समाधान के लिए कोई आसान तकनीक भी नहीं है । इसलिए हम बिल्कुल निराश नहीं हैं । वस्तुत: मसले के स्वरूप और इस तथ्य को देखते हुए कि यह मसला हम दोनों के लिए संवेदनशील है, हम समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वह स्वाभाविक है । अंतिम उपाय इन सिद्धांतों को और रुपरेखा को समाधान में परिवर्तित करना होगा ।

प्रश्न : क्या प्रधानमंत्री जापानी नेताओं के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग की संभावना पर विचार – विमर्श करेंगे

विदेश सचिव : मैं समझता हूं कि एनएसजी में सहमति के लिए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अनुमोदन के लिए सहयोग के प्रति हम जापान के बहुत आभारी हैं । आपको याद होगा कि आईएईए रक्षोपाय समझौते पर सर्वसम्मति थी । क्योंकि हम महसूस करते हैं, जापान के अपने विशेष इतिहास को देखते हुए जापान में यह विशेष रूप से संवेदनशील मसला था । इसलिए हम इसके लिए आभारी हैं । मुझे विश्वास है कि यह इस रूप में भी आएगा । यह वास्तव में जापान पर निर्भर करता है ।

प्रश्न : रंजीत के प्रश्न के क्रम में । एक ओर जीई और वेस्टिंग हाउस और दूसरी ओर हिटैची और तोशिवा के बीच संबंधों को देखते हुए क्या ऐसा नहीं है कि जब तक जापान भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं करता, 123 समझौता अथवा उससे कोई अन्य समझौता लागू नहीं हा सकता ? क्या ऐसा नहीं है कि आप इसे कार्यसूची में लाने के लिए सक्रिय रूप से काम रहे हैं ? क्या अब भी आप इससे बहुत दूर हैं ?

विदेश सचिव : मुझे विश्वास नहीं है कि यह बिल्कुल सही है । मैं समझता हूं वास्तविकता इस पर निर्भर करती है कि प्रत्येक कंपनी कहां निगमित है, किस कंपनी के साथ आपने क्या समझौता किया है । इसलिए जब यह समस्या आएगी, हम इसे देखेंगे ।

इस समय, इन सभी देशों में जिनके साथ हम समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, कंपनियों के साथ असैन्य परमाणु पहल के लिए व्यावसायिक व्यवस्थाएं करने और उन्हें लागू करने पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है ।

प्रश्न : क्या तोशिबा अथवा हितैची से सामग्री प्राप्त करने के लिए अलग द्विपक्षीय समझौते की आवश्यकता नहीं होगी ?

विदेश सचिव : जब तक हम व्यापक वाणिज्यिक व्यवस्था नहीं कर लेते, मैं नहीं समझता कि हमें कुछ और करने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि कंपनियां यह निर्णय लें कि वे कहां से आपूर्ति करती हैं और वे क्या करती हैं । मैं आश्वस्त हूं कि ये कंपनियां जो भी कानून उन

पर लागू होता है और सामान्यत: यह वही कानून होता है जहां वे निर्मित होती हैं, के तहत अपनी स्वयं के दायित्वों को ध्यान में रखेंगी ।

प्रश्न : मैं यही जानना चाहता हूं कि श्रीलंका की वास्तविक स्थिति पर भारत का क्या आकलन है । श्रीलंका की सेना लिट्टे के गढ़ में प्रवेश करने के कितने करीब है ?
विदेश सचिव : आप चाहते हैं कि विदेश सचिव से सैनिक जानकारी ली जाए ।

प्रश्न : नहीं नहीं । मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि इस स्थिति पर आपके क्या विचार हैं ।
विदेश सचिव : हम जो देखते हैं, वह वास्तव में एक मानवीय संकट है जो तमिल नागरिकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है क्योंकि यह उन्हीं क्षेत्रों में है जहां बड़ी संख्या में तमिल आबादी है । हम महसूस करते हैं कि इसका समाधान किए जाने की जरूरत है । किंतु श्रीलंका के लिए संघर्ष का समाधान करना और शांति लाना एक बड़ा मसला है जिसके लिए राजनीतिक समाधान आवश्यक है ।

सैनिक बल से इसका समाधान नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूं कि हमने पहले भी यही कहा था । अखंड श्रीलंका की रुपरेखा में कुछ राजनीतिक व्यवस्था की जानी है जिसमें सभी समुदाय सुविधाजनक महसूस करें और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ें । हम इसी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । श्रीलंका में जो स्थिति है उसका यही समाधान हो सकता है ।

प्रश्न : कुछ रिपोर्टें हैं कि चीन, पाकिस्तान के साथ परमाणु सहयोग करना चाहता है । क्या इससे भारत चिंतित होगा ?
विदेश सचिव : मैं समझता हूं कि हमने अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह अलग अलग देशों को निर्णय करना है कि वे अपनी – अपनी अप्रसार वचनबद्धताओं के अनुसार क्या करते हैं ; कि देशों का निश्चित रूप से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार है । किंतु यह अप्रसार को बढ़ावा देने के संदर्भ में होना चाहिए । यह एक ऐसा निर्णय है जो देशों को स्वयं लेना है । जब ये विशेष मामला सामने आएगा तो हम आपको विशेष उत्तर देंगे । किंतु यह हमारा सामान्य दृष्टिकोण है ।

प्रश्न : महोदय, श्रीलंका के मसले पर वापस आते हैं । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि श्रीलंका में पीड़त तमिल नागरिकों को दवाओं और खाद्य सामग्री की आवश्यकता है जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसाइटी के माध्यम से की जानी है । क्या हमें यह आपूर्ति करने में रेड क्रास सोसाइटी से कोई सहायता मिली है ?
विदेश सचिव : हम संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से और रेड क्रास के साथ और विभिन्न संगठनों के साथ काम कर रहे हैं जो उन क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं जहां आज युद्ध चल रहा है । दवाएं, अनिवार्य आपूर्ति, खाद्य सामग्री आदि लेकर पिछले सप्ताह अनेक बचाव दल गए हैं । और हम यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारी सहायता भी वहां तक पहुंचे ।

प्रश्न : रवि साहब, आपने कहा था कि भारत पहली बार शासनाध्यक्ष के स्तर पर शिखर बैठक में भाग ले रहा है । कोई विशेष उम्मीद ? कितने शासनाध्यक्ष इस शिखर बैठक में भाग ले रहे हैं ?
सचिव (पूर्व) : इस समय मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं कि कितने शासनाध्यक्ष इसमें भाग लेंगे । मैं अनुमान लगा सकता हूं कि विश्व की वर्तमान वित्तीय स्थिति देखते हुए अनेक नेता इसमें भाग लेना चाहेंगे । यह कई दृष्टिकोणों से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिखर बैठक है क्योंकि जब हम एशिया की स्थिति की ओर देखते हैं, एएसईएम के एशियाई हिस्से में अनेक विकासशील देश हैं जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से काफी हद तक प्रभावित हैं और उनकी अपनी विकास प्रक्रिया भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है । एक विषय जिस पर विश्व नेताओं का ध्यान विशेष रूप से जाएगा वह यह है कि वित्तीय मोर्चे पर उन्हें पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकासशील देशों में स्थायी विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए । ऐसे कुछ देश यूरोप में भी हैं ।

सरकारी प्रवक्ता : आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

(समाप्त)

भारत और जापान के बीच सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी को आगे बढ़ाने से संबद्ध संयुक्त वक्तव्य

अक्तूबर 22, 2008

1. भारत और जापान के प्रधान मंत्री वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन के लिए 22 अक्तूबर 2008 को टोक्यो में मिले। उन्होंने इस विचार पर सहमति व्यक्त की कि एशिया के दो बड़े देश, भारत और जापान जिनके साझे मूल्य और हित हैं, को एशिया तथा संपूर्ण विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय विषयों पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने इस प्रयोजनार्थ तथा भारत-जापान संबंधों की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2006 में स्थापित सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी के महत्व की पुन: पुष्टि की।

2. दोनों प्रधानमंत्रियों ने सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी के नए आयामों के रोड मैप के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा दोनों पक्षों के बीच संयुक्त प्रयासों के जरिए की गई सतत प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हितों की साझी समानता के आधार पर इस संबंध को व्यापक और गहन बनाने के संबंध में अपने प्रयासों को जारी रखने की वचनबद्धता व्यक्त की जिससे कि इस क्षेत्र की भावी रूपरेखा के एक अनिवार्य आधार स्तम्भ के रूप में इसका विकास किया जा सके।

3. दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले भावी सहयोग पर हुए अध्ययन का स्वागत किया और इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा जारी की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त घोषणा के आधार पर किया जाने वाला भावी सहयोग एशिया और विश्व में शांति और समृद्धि के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र इस घोषणा के आधार पर सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने हेतु विशेष उपायों के साथ एक कार्य योजना तैयार करने का अनुदेश अपने-अपने मंत्रियों को दिया।

4. दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने-अपने विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्षिक सामरिक वार्ता तथा अन्य स्तरों पर होने वाली नीतिगत वार्ताओं को और गहन बनाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने रक्षा आदान-प्रदानों और सहयोग की प्रक्रिया में निरन्तर हो रहे उन्नयन का स्वागत किया और अपने-अपने रक्षा मंत्रियों को मई, 2006 में जारी संयुक्त वक्तव्य के आधार पर अपनी बातचीत और सहयोग को समृद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने संस्थापित द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों के योगदान का भी स्वागत किया तथा उनसे अपने उपयोगी कार्यों को जारी रखने का आह्वान किया।

5. दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार, जिसके वर्ष 2010 तक 20 बिलियन अमरीकी डालर का आकार प्राप्त कर लेने की आशा है, के विकास पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने आर्थिक भागीदारी करार/व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर हुई पर्याप्त प्रगति का स्वागत किया और इस बात की आशा व्यक्त की कि इन वार्ताओं को यथासंभव शीघ्र परिणति पर लाया जाएगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस संबंध में अपना विश्वास व्यक्त किया कि आर्थिक भागीदारी करार/व्यापक आर्थिक भागीदारी करार, पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा और इनसे आर्थिक भागीदारी की पूर्ण क्षमता प्राप्त की जा सकेगी।

6. दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच विद्यमान स्थायी निवेश संबंधों, विशेष रूप से भारत में जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पर्याप्त उपस्थिति पर खुशी व्यक्त की। हाल के वर्षों में जापान द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पर्याप्त वृद्धि होने के साथ ही यह निवेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। निवेश की आगामी योजनाएं भी काफी प्रभावशाली हैं। इस संबंध में दोनों नेताओं ने भारत में जापान के लघु एवं मझोले उपक्रमों द्वारा निवेश को दिए जा रहे समर्थन के लिए जेटरो और अन्य संगठनों के प्रयासों का स्वागत किया। इसके अतिरिक्त दोनों प्रधानमंत्रियों ने आशा व्यक्त की कि आगामी वर्षों में प्रगति की यह दर कायम रहेगी।

7. दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की कि जापान से प्राप्त आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ने भारत के आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान दिया है और इसने जापान के लिए भारत के लोगों में सद्भावना का सृजन किया है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्ति की कि जापान से प्राप्त आधिकारिक विकास सहायता से भारत में गरीबी उपशमन एवं आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना विकास तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान एवं मानव संसाधन विकास में उत्तरोत्तर योगदान मिलता रहेगा। भारत के प्रधान मंत्री ने भारत के विकास में जापानी जनता की उदारता के लिए उनकी भूरि-भूरि सराहना की।

8. दोनों प्रधान मंत्री इस बात के संबंध में संतुष्ट थे कि दिसंबर, 2006 में आरम्भ की गई विशेष आर्थिक भागीदारी पहल से द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना आरम्भ हो गया है। इससे व्यवसाय के नए अवसरों का भी सृजन हुआ है।

9. दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक भागीदारी योजना के संबंध में जापान की विशेष शर्तों का उपयोग करते हुए जापानी आधिकारिक विकास सहायता ऋण के साथ भारत-जापान सहयोग की एक अग्रणी परियोजना के रूप में समर्पित फ्रेट गलियारा (डीएफसी) परियोजना के

पश्चिमी गलियारे का कार्य पूरा करने के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की और साथ ही उन्होंने इस परियोजना के प्रथम चरण (रेवाड़ी – बड़ोदरा सेक्टर) की पहल करने की अपनी-अपनी तत्परता का प्रदर्शन किया।

इस संबंध में जापानी पक्ष ने विद्युत ट्रैक्शन प्रणाली से समर्पित फ्रेट कॉरीडोर के पश्चिमी कॉरीडोर को प्रचालित करने के भारत के निर्णय का स्वागत किया। यह सहायता इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए आधिकारिक विकास सहायता ऋण के जरिए आरम्भ होगी और प्रथम चरण के लिए ऋण की कुल मात्रा का वर्तमान अनुमान लगभग 450 बिलियन येन की है जो अंतिम परियोजना डिजाइन पर आधारित है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सम्पूर्ण पश्चिमी गलियारे के लिए सहायता को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए मिलकर कार्य करने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त की।

10. दोनों प्रधानमंत्रियों ने विचार व्यक्त किया कि दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना (डीएमआईसी), जो समर्पित फ्रेट गलियारा परियोजना के पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है, में भारत-जापान आर्थिक क्रियाकलापों के समीकरण में परिवर्तन ला देने की क्षमता है तथा उन्होंने इस कार्य को और आगे ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) तथा भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) / दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का स्वागत किया और इस बात की पुष्टि की कि वे संयुक्त रूप से एक परियोजना विकास कोष की स्थापना करने के लिए मिलकर कार्य करना जारी रखेंगे।

दोनों पक्षों ने संभारतंत्र मानव संसाधन विकास, विद्युत उत्पादन तथा बस्तियों के विकास के क्षेत्र में दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में 5 आरंभिक परियोजनाओं में जापानी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने प्रमुख आयोजना कार्यों के साथ-साथ परियोजना से जुड़े राज्यों में शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन हेतु कुछ चुनिंदा परियोजनाएं आरम्भ करने के दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम की पहल का भी स्वागत किया।

उन्होंने दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना के संबंध में समग्र सहयोग पर और चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की जिससे कि पारस्परिक रूप से लाभकारी ऐसे व्यावसायिक संबंधों को संवेग मिल सके, जो दोनों देशों के दीर्घावधिक हितों का संवर्धन करने में समर्थ हों।

11. दोनों प्रधानमंत्रियों ने उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया और इस क्षेत्र में सहयोग की असीम संभावनाओं पर गौर किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी-अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित मामलों का समाधान करते हुए दो तरफा उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु द्विपक्षीय परामर्श जारी रखने के महत्व को स्वीकार किया।

12. दोनों नेताओं ने अगस्त, 2007 में हस्ताक्षरित पर्यावरण संरक्षण तथा ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग संवर्धन से संबद्ध संयुक्त वक्तव्य का स्मरण किया और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की गति को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत-जापान मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत हुई प्रगति का स्वागत किया जिसमें विशेष रूप से भारत में क्षेत्रीय ऊर्जा प्रभाविता केंद्रों की स्थापना, कोयला एवं विद्युत क्षेत्र में व्यापक सहयोग को बढ़ावा देने के जरिए ऊर्जा प्रभाविता एवं संरक्षण क्षेत्र में सहयोग संवर्धित करने की पुष्टि की गई।

उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि इस वार्ता तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि वे अपने-अपने देशों की नाभिकीय ऊर्जा नीतियों के संबंध में सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। उन्होंने जापान के नवीन ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी विकास संगठन (नेडो) तथा भारत के ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा भारत-जापान ऊर्जा मंच के अंतर्गत हुई बैठकों की प्रगति का स्वागत किया और व्यावसायिक आधार पर द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को विस्तारित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार किया।

13. दोनों मंत्रियों ने जून, 2008 में आयोजित शहरी विकास से संबद्ध भारत-जापान संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक से प्राप्त उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया और कार्यकारी दल की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करते रहने की अपनी मंशा की पुष्टि की।

14. दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह विचार व्यक्त किया कि वे अनुसंधान, सहयोग तथा वाइड बैंड बेतार प्रौद्योगिकी के शुभारंभ सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे।

15. दोनों प्रधानमंत्रियों ने उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रमुख मंच (बीएलएफ) की दूसरी बैठक के उपरान्त प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का स्वागत किया। उन्होंने व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को गहन बनाने में दोनों देशों के व्यवसाय और उद्योग जगत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने अपने-अपने देशों से संबंधित अधिकारियों से व्यावसायिक प्रमुख मंच की अनुशंसाओं की त्वरित जांच और क्रियान्वयन करने का आहवान किया।

16. दोनों प्रधानमंत्रियों ने सांस्कृतिक, शैक्षिक, युवा तथा लोगों से लोगों के स्तरों पर होने वाले आदान-प्रदानों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने पूर्व एशिया छात्र एवं युवा आदान-प्रदान नेटवर्क कार्यक्रम तथा आसो कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के बीच हो रहे संवर्धित आदान-प्रदान पर संतोष व्यक्त किया और प्रगति की इस प्रवृत्ति को कायम रखने की अपनी वचनबद्धता को नवीकृत किया।

17. दोनों प्रधानमंत्रियों ने जापान की सहायता से एक नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना किए जाने में संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए गठित भारत-जापान कार्यकारी दल के कार्यों की सकारात्मक समीक्षा की और कार्यकारी दल द्वारा उन्हें पेश की गई रिपोर्ट का स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हैदराबाद में एक नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना में सहयोग की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की, जो जापान से प्राप्त विभिन्न योगदानों के जरिए भारत में शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले संयुक्त प्रयासों का एक प्रतीक होगा।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि ऐसे सहयोग के लिए शैक्षिक विशेषज्ञों सहित दोनों पक्षों के संबंधित पक्षकारों द्वारा आपसी लाभ के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होगी।

18. दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस विषय पर दिसंबर 2006 में संपन्न ज्ञापन के अनुसरण में जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं निर्माण संस्थान के विकास में सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी प्रयास करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

19. दोनों प्रधानमंत्रियों का यह मत था कि विश्व स्तर पर ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित, सतत एवं स्वच्छ स्रोत के रूप में नाभिकीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण और अप्रसार प्रयासों को संवर्धित किया जाना चाहिए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व का स्वप्न साकार करने के साझे लक्ष्य की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के महत्व को भी दोहराया।

20. दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझे हित के विषयों पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा पूर्वी एशियाई समुदाय की स्थापना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्रीय, आर्थिक एकीकरण को गहन बनाने के लिए एक मुक्त, समग्र, पारदर्शी मंच के रूप में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अपने समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने आगामी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इस लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने आसियान तथा पूर्वी एशिया आर्थिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना का स्वागत किया और इस वर्ष दिसंबर में पूर्वी एशिया में व्यापक आर्थिक भागीदारी (सीईपीईए) पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट का हवाला दिया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग बनाए रखने के महत्व की पुष्टि की। उनका यह मत भी था कि स्थाई और अस्थाई दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 28 फरवरी, 2009 तक अंतर-सरकारी बातचीत आरम्भ करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय का स्वागत किया।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वास्तविक सुधार की दिशा में सकारात्मक रूप से परन्तु त्वरित गति से आगे बढ़ने में घनिष्ठ सहयोग जारी रखने का निर्णय भी लिया जिससे कि इस वैश्विक संस्था को और भी प्रातिनिधिक, विश्वसनीय तथा प्रभावी बनाया जा सके।इस संदर्भ में उन्होंने जी-4, द्विपक्षीय विचार-विमर्शों तथा संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ बातचीत के महत्व पर बल दिया।

21. दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों और तत्वों की भर्त्सना की तथा इस बात की पुष्टि की कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न एक गम्भीर खतरा है और साथ ही उन्होंने इस नासूर का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल तथा संयुक्त राष्ट्र के तंत्रों के जरिए आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग को संवर्धित करने के अपने संकल्प को रेखांकित किया।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभिसमय पर चल रही बातचीत को शीघ्रातिशीघ्र तार्किक परिणति पर ले जाने की अपनी इच्छा की पुष्टि की।

22. दोनों प्रधानमंत्रियों का यह विचार था कि वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में वित्तीय कठिनाइयों सहित अनिश्चितता का एक माहौल बना हुआ है और दोनों देशों को इस क्षेत्र तथा सम्पूर्ण विश्व में स्थिरता और विकास के लिए अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनहोंने तेल की उच्च और अस्थिर कीमतों के कारण पड़ने वाले प्रभावों, जिसके कारण वैश्विक विकास में भी बाधा पहुंच रही है, के प्रशमन के लिए तेल की खपत और उत्पादन करने वाले सभी देशों द्वारा संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार किया।

उन्होंने इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की कि विश्व में खाद्य की कीमतें अभी भी काफी अधिक हैं और साथ ही उन्होंने वैश्विक खाद्य

सुरक्षा की चुनौती का सामना करने के लिए बेहतर सहयोगी प्रयास किए जाने का आहवान किया। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन तथा दोहा विकास कार्य सूची के संबंध में चल रही वार्ता की स्थिति पर भी चर्चा की तथा एक संतुलित एवं व्यापक परिणाम के साथ वार्ताओं की सफल परिणति की दिशा में अपना सहयोग जारी रखने की अपनी इच्छा की पुष्टि की।

23. दोनों प्रधानमंत्रियों ने बाली कार्य योजना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और फिलहाल, वर्ष 2012 तथा इसके आगे तक के लिए एक लोचनीय न्यायसंगत और प्रभावी सहमत परिणाम, जिसमें सभी देश भाग ले सकें, के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जापानी पक्ष ने "जलवायु परिवर्तन से संबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना" के संबंध में भारत की हाल की घोषणा का स्वागत किया और भारतीय पक्ष ने इस मुद्दे पर जापान द्वारा की गई विभिन्न पहलकदमियों का स्वागत किया।

दोनों प्रधान मंत्री इस विचार से सहमत थे कि सभी देशों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आकलन राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा साझे परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं अपनी-अपनी क्षमताओं के सिद्धांत के अनुसार विविध मानदण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने वैश्विक उत्सर्जन में कमी लाने, होने वाली बातचीत में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों द्वारा दीर्घावधिक वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करने की इच्छा की पुष्टि की तथा अगले वर्ष आयोजित होने वाली सीओपी-15 के संबंध में घनिष्ठ सहयोग करने की वचनबद्धता व्यक्त की।

इस संबंध में उन्होंने वैश्विक उत्सर्जन में वर्ष 2050 तक कम से कम 50 प्रतिशत की कमी लाने के विजन को यूएनएफसीसीसी के सभी पक्षकारों के साथ बांटने की इच्छा पर गौर किया। उन्होंने इस बात को भी गौर किया कि सतत विकास के लिए लागत न्यायसंगत तरीके से वहन करने की प्रक्रिया वार्ता मार्गनिर्देशक होने चाहिए। ऊर्जा प्रभाविता सुनिश्चित करने तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत और जहां कहीं आवश्यक हो, क्षेत्र विशिष्ट लक्ष्यों और कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए ऊर्जा प्रभाविता और संरक्षण को बढ़ावा देने की पुष्टि की।

इस बात को स्वीकार करते हुए कि ऊर्जा प्रभाविता में सुधार लाने जैसे उपायों के जरिए वैश्विक उत्सर्जन में कमी लाने के एक उपयोगी औजार के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उन्होंने अन्य देशों के सहयोग से सहकारी क्षेत्रीय दृष्टिकोणों एवं क्षेत्र विशेष कार्यों के व्यावहारिक विकास पर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया जिसकी पुष्टि भारत-जापान मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता की तीसरी बैठक में की गई थी। उन्होंने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संपूरकता को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया और विकासशील देशों में अनुकूलन उपायों के लिए संसाधन निर्धारित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

वे इस विचार से सहमत थे कि भारत और जापान को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर निश्चित रूप से मिलकर कार्य करना चाहिए।

24. भारत के प्रधान मंत्री ने जापान की सरकार द्वारा उन्हें और उनके प्रतिनिधिमण्डल को दिए गए आतिथ्य सत्कार की सराहना की। उन्होंने जापान के प्रधान मंत्री को वर्ष 2009 में आयोजित होने वाले अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राजनयिक माध्यमों द्वारा निर्धारित की जाने वाली आपसी सुविधाजनक तारीकों को नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया।

डा. मनमोहन सिंह	श्री तारो असो
भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री	जापान के प्रधान मंत्री

टोक्यो, 22 अक्तूबर, 2008

जापान और 7वीं एएसईएम बीजिंग शिखर बैठक के लिए अपने प्रस्थान के समय प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

अक्तूबर 21, 2008

"मैं, भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर बैठक के लिए 22-23 अक्तूबर को जापान जाऊंगा ।

मैं, जापान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध मानता हूं । भारत और जापान, एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं जिनके अनेक समान साझा हित हैं और समान मूल्यों का समर्थन करते हैं । मजबूत भारत-जापान संबंध, उभरती एशियाई सुरक्षा संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एशिया एवं पूरी दुनिया की शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देंगे ।

अपनी इस जापान यात्रा के दौरान, मुझे जापान के सम्राट एवं साम्राज्ञी से भेंट करने का भी सौभाग्य मिलेगा । भारत के घनिष्ठ मित्र, प्रधानमंत्री तारो आशो के साथ अपने विचार-विमर्श में हम पिछले एक वर्ष में अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और अगले वर्ष के लिए कार्यसूची तय करेंगे । यद्यपि, पिछले चार वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है किंतु अब-भी काफी क्षमता बाकी है जिसका दोहन किया जाना है ।

जापान, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है । मेरी यात्रा से अलग, जापान-भारत व्यापारिक नेता मंच की दूसरी बैठक होगी । मैं निपोन कीडानरेन द्वारा आयोजित की जा रही जापान के व्यापारिक नेताओं की बैठक को संबोधित करने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

अपनी प्रथम जापान यात्रा के पश्चात् मैं 7वीं एएसईएम शिखर बैठक के लिए बीजिंग जाऊंगा । यह पहला अवसर है जब भारत एएसईएम शिखर बैठक में भाग लेगा । इस शिखर बैठक में हमारी भागीदारी एशिया और यूरोप के देशों के साथ हमारे प्रगाढ़ और बढ़ते संबंधों का स्वाभाविक परिणाम है ।

एएसईएम शिखर बैठक से अलग राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ बैठक के अलावा, मुझे दुनिया के दूसरे नेताओं से भी मिलने का अवसर मिलेगा जिनमें बुलगारिया के राष्ट्रपति पूर्वानोव, मंगोलिया के राष्ट्रपति इंखबायर, जर्मनी की चांसलर मार्केल, इटली के प्रधानमंत्री बरलूसकोनी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्गूयान तान डंग शामिल हैं ।"

नई दिल्ली
21 अक्तूबर, 2008

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर निष्पादन की ओर आगे बढ़ा – जापान की ओडीए सहायता को अंतिम रुप दिया गया

अक्तूबर 22, 2008

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसंरचना विस्तार परियोजना के रुप में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय रेलवे की समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की कल्पना की गई थी । कच्चे माल उत्पादन के क्षेत्रों को उपभोक्ता केंद्रों से जोड़ने और दोनों को महापत्तनों से जोड़ते हुए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, भारतीय उद्योग क्षेत्र में समग्र वृद्धि दर और क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा ।

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर में कुल 3288 कि0मी0 लंबे दो रेलवे कॉरिडोर, पश्चिमी (1483 कि0मी0) और पूर्वी (1805 कि0मी0) शामिल हैं । पश्चिमी कॉरिडोर की अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रु0 और पूर्वी कॉरिडोर की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रु0 है । इस परियोजना को 5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है । 920 कि0मी0 लंबे रेवाड़ी - वड़ोदरा खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पहले ही अंतिम रुप दे दिया गया है ।

जापान सरकार ने प्रथम चरण के लिए 17045 करोड़ रु0 के ओडीए ऋण का वादा किया है । यह धनराशि, रेवाड़ी - वड़ोदरा खंड की कुल लागत का 62% है । जापान सरकार पश्चिमी कॉरिडोर के शेष खंड के लिए भी इसी प्रकार का ऋण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ।

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के पूर्वी कॉरिडोर के वित्त पोषण के लिए भारतीय रेलवे, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के बीच विचार-विमर्श उन्नत स्तर पर है । यद्यपि, विश्व बैंक से 2.5 से 3 अरब अमरीकी डालर के ऋण का अनुमान है, एशियाई विकास बैंक के साथ परियोजना के लिए तकनीकी सहायता पर विचार किया जा रहा है ।

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के दोनों कारिडोरों पर कार्य चालू वित्त वर्ष में प्रारंभ होना है । शुरु किए जाने वाले प्रथम कार्य, पश्चिमी कॉरिडोर के 200 कि0मी0 और पूर्वी कॉरिडोर के 105 कि0मी0 पर 54 महत्वपूर्ण पुल हैं । इन उप-परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श और टर्नकी ठेकों के लिए निविदाएं पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं और इनकी जांच की जा रही है ।

नई दिल्ली
22 अक्तूबर, 2008

एएसईएम के कार्यकारी दोपहर भोज के अवसर पर प्रधान मंत्री का हस्तक्षेप

सितम्बर 25, 2008

25 अक्तूबर, 1245 बजे से प्रारम्भ

(प्रधान मंत्री पहले वक्ता थे)

प्रधान मंत्री: हम लोगों के बीच अत्यंत उपयोगी चर्चा हुई। हम लोगों के बीच इस बात पर पूर्ण सहमति थी कि एएसईएम वैश्विक मुद्दों के समाधान हेतु एक शक्तिशाली मंच है।

हम सभी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के संबंध में भी समान विचार रखते हैं। परन्तु वैश्विक वित्तीय संकट से जुड़े मुद्दों में संलिप्त होने के कारण हमें सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015 का समय निर्धारित किया गया है और वर्ष 2008 में आधा समय बीच चुका है तथापि जिस प्रकार से बात आगे बढ़ रही है, हममें से कम लोग ही विश्वास करेंगे कि इन लक्ष्यों को प्राप्त भी किया जा सकेगा। एक सहभागी ने इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित राशि का उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव मात्र 16 बिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता सुनिश्चित करने में समर्थ हो पाए हैं। यह हमारे असमान विश्व को परिलक्षित करता है।

हमें सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में चिंतित होना चाहिए जिसके लिए और भी सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता पर बाद में चर्चा करने की बजाय यदि हमें वर्ष 2015 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इसके लिए और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी।

धन्यवाद।

भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा

अक्तूबर 22, 2008

भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने;
इस बात की पुष्टि करते हुए कि भारत और जापान के बीच विद्यमान संबंध की जड़ें इस क्षेत्र और सम्पूर्ण विश्व में उदीयमान पर्यावरण के संबंध में अपनी-अपनी समान भावनाओं से मिलती हैं; लोकतंत्र, मुक्त समाज, मानवाधिकारों तथा विधिसम्मत शासन के प्रति अपनी साझी वचनबद्धता को स्वीकार करते हुए; एशिया तथा इसके आगे शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने में एक दूसरे के योगदान के प्रति अपने-अपने गहरे सम्मान की पुष्टि करते हुए;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि भारत और जापान एक दसरे की प्रगति और समृद्धि में पारस्परिक भागीदार हैं और यह कि एक सुदृढ़ एवं समृद्ध भारत जापान के हित में है तथा एक सुदृढ़ और समद्ध जापान भारत के हित में है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि संचार के समुद्री लाइनों की सुरक्षा में भारत और जापान का साझा हित है; हिन्द महासागर में जापानी समुद्री स्वरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि किए जाने सहित भारत और जापान द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने से जुड़े प्रयास आतंकवाद का उन्मूलन करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के एक महत्वपूर्ण भाग हैं;

एक शांतिपूर्ण नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व का निर्माण करने के प्रयास के भागीदारों के रूप में निशस्त्रीकरण और अप्रसार के प्रति अपनी साझी वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए तथा अप्रसार के विरुद्ध मिल-जुलकर कार्य करते हुए; के प्रति अपनी साझी वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी एवं अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता के विस्तार सहित संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की अपनी साझी वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए; एक ऐसी सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी की स्थापना की पुष्टि करते हुए जो समान, दीर्घावधिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सामरिक हितों, आकांक्षाओं तथा चिन्ताओं द्वारा प्रेरित हों;

पारस्परिक सहयोग का निरन्तर और गुणात्मक उन्नयन किए जाने के महत्व को स्वीकार करते हुए; दोनों देशों के विदेश मामले, रक्षा तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच व्यावहारिक सहयोग में वृद्धि करते हुए भविष्य में मिलकर कार्य करने की वचनबद्धता व्यक्त करते हुए; दोनो देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग के संवर्धन हेतु एक व्यापक रूपरेखा सृजित करने का निर्णय लिया है।

सहयोग के तत्व
भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगा:

1. एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय तथा दीर्घावधिक सामरिक एवं वैश्विक मुद्दों पर सूचना का आदान-प्रदान तथा नीतिगत समन्वयन।
2. एशिया, विशेष रूप से पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच और रि-कैप प्रक्रियाओं में बहुपक्षीय ढाचों के भीतर द्विपक्षीय सहयोग।
3. दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मई 2000 में हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य की रूपरेखा के अंतर्गत रक्षा वार्ता में सहयोग।
4. तट रक्षकों बलों के बीच सहयोग।
5. परिवहन सुरक्षा।
6. आतंकवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध युद्ध।
7. शांति रक्षा एवं शांति निर्माण में अनुभवों का आदान-प्रदान।
8. आपदा प्रबंधन।
9. नि:शस्त्रीकरण तथा अप्रसार

सहयोग के तंत्र

दोनों देशों के बीच ऊपर लिखित सहयोग को ठोस रूप देने के उद्देश्य से निम्नलिखित तंत्रों को शामिल किया जाएगा।

1. निम्नलिखित के जरिए दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच परामर्श किए जाएंगे:
   I. विदेश मंत्रिस्तरीय सामरिक वार्ता;
   II. भारत के विदेश सचिव तथा जापान के उप-विदेश सचिच के बीच बैठक;
   III. महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर पर नि:शस्त्रीकरण तथा अप्रसार के संबंध में बातचीत;
   IV. ट्रैक 1.5 सामरिक वार्ता।

2. निम्नलिखित सहित अन्य तरीकों से दोनों देशों के रक्षा प्राधिकरणों के बीच सहयोग किए जाएंगे:
   I. रक्षा मंत्रियों के बीच बैठकें;
   II. भारत के रक्षा सचिव तथा रक्षा नीति वार्ता सहित जापान के रक्षा उप-मंत्री के बीच बैठकें;
   III. महासचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर सैन्य वार्ताएं;
   IV. सेवा प्रमुखों की यात्राओं का आदान-प्रदान;
   V. दोनों देशों के नौसेना स्टाफ के बीच बातचीत;
   VI. द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यासों सहित सेनाओं के बीच आदान-प्रदान;
   VII. अपने-अपने रक्षा संस्थानों (उदारण के लिए भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कालेज, जापान राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान) के लिए छात्रों एवं अनुसंधानकर्ताओं का आदान-प्रदान।

3. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके जापानी समकक्ष के बीच विचार-विमर्शों का आयोजन किया जाएगा।
4. दोनों देशों के तटरक्षक बल भारतीय तटरक्षक बल एवं जापानी तटरक्षक बल के बीच संपन्न सहयोग ज्ञापन के अनुसरण में दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच आयोजित हाने वाले संयुक्त अभ्यासों तथा बैठकें के जरिए समुद्री सुरक्षा, समुद्री संरक्षा तथा समुद्री पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने में सहयोग को बढ़ावा देना जारी रखना।
5. परिवहन सुरक्षा के संबंध में समुदीय प्राधिकरणों तथा निजी क्षेत्रों के बीच नौवहन नीति मंचों का तथा दोनों देशों के रेलवे प्राधिकरणों के बीच परामर्शों का आयोजन किया जाएगा।
6. महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर पर व्यापक सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया जाएगा।
7. दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों सहित अन्य प्रासंगिक सरकारी कार्यालयों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल जैसे अन्य तरीकों से आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय विचार-विमर्श किए जाएंगे।
8. दोनों देशों की वित्तीय सूचना इकाइयों के बीच धन के संदेहास्पद तथा गैर-कानूनी लेनदेन एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के संबंध में सूचनाओं का आदान-प्रदान किए जाने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाएगी।
9. भारत में सुनामी आपदा मंच बनाने में सहयोग किया जाएगा।
10. दोनों पक्ष दोनों देशों में आपदा निरोध, इसकी तैयारी, इससे संबंधित ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देंगे।
11. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा जापान एयरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) के बीच सहयोग किया जाएगा।

क्रियान्वयन

भारत और जापान उपर्युक्त क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपायों के साथ एक कार्य योजना तैयार करेंगे जिसकी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दोनों प्रधानमंत्रियों को सौंपी जाएगी।

टोक्यो
20 अक्तूबर, 2008

डा. मनमोहन सिंह
भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री

श्री तारो असो
जापान के प्रधान मंत्री